terms and conditions for giving such permission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) and (b) Government have recently decided in principle to permit Indian entrepreneurs including FERA and MRTP companies to establish Joint ventures in deep sea fishing subject to the exemption/clearance to be given by the Deptt. of Company Affairs, as prescribed under the relevant Acts and rules, in order to achieve the optimum utilisation of marine resources in the Indian Exclusive Economic Zone (EEZ) with a view to increasing the exports of marine products.

The terms and conditions for such joint ventures include that such joint venture companies should accquire vessels (i) of 20M and above, register the vessel in their name in India and fly the Indian flag, (ii) either through outright purchase or on deferred payment as specifically approved by the Government and (iii) also on long-term lease (8-10 years).

Trade between Indian and Yugoslavia

702. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the present volume of bilateral trade between India and Yugoslavia;

(b) whether any specific plan has been formulated to increase the bilateral trade between the two countries; and

(c) if so, what are the main items and commodities to be exported to Yugoslavia?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P.R. RAS MUNSHI): (a) to (c) After the latest figures available, the present volume of trade between India and Yugoslavia is as under:—

(Rs. in crores)

	1984-85	1985-86(P)
Exports to Yugoslavia	21.68	23.29
Imports from Yugoslavia	58.89	75.97

While no specific plan has been drawn, efforts are being made by both the countries to increase the volume of trade by measures such as Linked deal arrangement, exchange of trade and industry delegations, participation in trade fairs and encouragement for long-term contracting and it is proposed to increase the trade turnover to about US $ 200 million in 1987. The main items of export to Yugoslavia are Coffee, Tea, Black pepper and other spices, Deoiled cakes, HPS groundnut, Mica, Wire ropes. Auto parts and components, Tyres, Bicycle parts, Cotton textiles, Jute goods etc. Efforts are being made to increase export of manufactured and engineering products from India to Yugoslavia.

भारत के संविधान का हिन्दी रूपान्तर

703. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के संविधान के हिन्दी रूपान्तर का कोई महत्व नहीं है क्योंकि न्यायालयों में इसे प्रमाणिक नहीं माना जाता केवल अंग्रेजी पाठ को ही प्रमाणिक माना जाता है ; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो सरकार संविधान के अंग्रेजी पाठ के स्तर का ही हिन्दी रूपान्तर तत्काल तैयार करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) यह सही है कि न्यायालय संविधान के हिन्दी रूपान्तर को प्रमाणिक नहीं मानते ।

(ख) संविधान का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के उपबंध के लिये संविधान में संशोधन का विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया है ।

पर्यटनों को उद्योग घोषित करना

704. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पर्यटन को उद्योग घोषित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहें हैं और घरेलू व विदेश पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस अवधि के दौरान किन स्थानों का विकास किए जाने की संभावना है ; और

(ख) बिहार में झीलों, पहाड़ियों, जंगलों और गर्म पानी के चश्मों को जिनमें अनेकों देश व विदेश में प्रसिद्ध हैं विकसित करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एप्रोच पेपर को अनुमोदित करते समय यह सिफारिश की थी कि पर्यटन को एक उद्योग का उर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। इस सिफारिश के अनुकरण में, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पर्यटन की उद्योग के रूप में घोषित करने के लिए निरंतर अनुरोध किया जा रहा हैं ताकि जो रियायतें अन्य उद्योगों को उपलब्ध हैं वे पर्यटन से संबद्ध कार्यकलापों पर भी लागू हो सकें। अभी तक हिमाचल प्रदेश, मेघालय , उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु, हरियाणा और बिहार की सरकारों ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया हैं जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सरकारों ने होटल को उद्योग के रूप में घोषित किया हैं ।

एक स्थान को पर्यटक संभाव्यता, एक केन्द्र की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या, धन-राशि की उपलब्धता और परपर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्र के परामर्श से पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए केन्द्रों का चयन किया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन आधार संरचना का विकास करने के लिए 80–100 केन्द्रों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

(ख) पहले से चली आ रही स्कीमें और बिहार में आधार-संरचना का विकास करने के लिए रिलीज की गई धनराशि इस प्रकार हैं–:

(लाख रुपए में)

स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. बेतला में सधे हुए हाथी	1.50	1.35
2. हजारीबाग में मिनी बस	2.67	2.40
3. तिलैया बांध के लिए नौकाएं	6.12	6.12
4. बेतला में वन गृह	46.76	40.00
5. गौतम वन का विकास	20.00	18.00
6. राजगीर में अल्पाहार गृह	5.04	2.50
7. मानेर शरीफ में अल्पाहार गृह	3.43	3.00

हीरों आदि का निर्यात

705. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरों, स्वर्ण भूषणों